दिनांक 17.08.2016 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में नॉर्थ एवं साउथ बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में बिजली पदाधिकारियों, सभी जिला के जिला पदाधिकारियों एवं सभी प्रमण्डलीय आयुक्त के साथ सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारियों एवं बिजली पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में यह बात प्रकाश में आई कि कई जिलों में बाढ़ की समस्या के मद्देनजर जिले के जिला पदाधिकारी बाढ़ की समस्या का समाधान करने में लगे हुए थे, जिसके फलस्वरुप मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत हाउस होल्ड सर्वे के कार्य की प्रगति धीमी थी। ग्रामीण हाउस होल्ड सर्वे के कार्य में 6 जिले यथा कटिहार, अररिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, जमुई और मुंगेर में प्रगति अच्छी नहीं है। 6 जिले यथा शेखपुरा, नालन्दा, बेगुसराय, नवादा, बक्सर और शिवहर सबसे अच्छी स्थिति में है। जिला पदाधिकारियों से हाउस होल्ड सर्वे के कार्य में तेजी लाने और लक्ष्य के अनुरूप समय पर कार्य पूरा करने का अनुरोध किया गया।

<u>प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को दिये गये निदेशः–</u>

1. अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि मुंगेर जिले के शत–प्रतिशत विद्युतीकरण के कार्य की समीक्षा के दरम्यान ज्ञात हुआ कि इस जिले में हाउस होल्ड सर्वे के कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। अतः व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर ससमय सर्वे कार्य कराया जाय।

2. सभी कनीय विद्युत् अभियन्ता को किये गये सर्वे को सत्यापित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्हें अनुश्रवण का कार्य भी करना है। किये गये सर्वे कार्यों की जाँच के दौरान जितने भी त्रुटि पाये गये हैं, उसका सुधार शीघ्र करवाया जाय।

3. यह पाया जा रहा है कि कई सर्वेकर्त्ता अपना डाटा बढ़ाने के लिए दोबारा entry कर देते हैं, जिसके कारण भविष्य में कठिनाई आयेगी। अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. हाउस होल्ड सर्वे के काम में लगे कर्मचारियों को इस कार्य हेतु भ्रमण करने, इंटरनेट पैक recharge तथा मोबाईल के सुचारू रूप से काम करने हेतु पावर बैंक की उपलब्धता इत्यादि पर होने वाले खर्च की भरपाई हेतु दो किश्तों में रू0 4000.00 (रूपये चार हजार) प्रति कर्मचारी को दिया जायेगा। इसमें रू0

2000/– प्रथम किश्त के रूप में तथा 2000/– रूपये कार्य समाप्ति के पश्चात दिया जायेगा। यह राशि संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को जल्द विमुक्त कर दी जायेगी।

5. <u>प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० एवं प्रबंध निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा बताया गया कि:–</u>

(क) संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिन गाँवों में बी०पी०एल० परिवार हैं, वहाँ विद्युतीकरण के साथ–साथ सभी बी०पी०एल० परिवारों को कनेक्शन दिया जाय। साथ ही जहाँ विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है वहाँ विद्युतीकरण के साथ–साथ बी०पी०एल० घरों में बिजली कनेक्शन भी देते जायें।

(ख) जिन स्थानों से Unmetered connection और defective meter का लिस्ट प्राप्त हुआ है, उसकी भी समीक्षा की जाय। संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि Unmetered connection और defective meter वाले उपभोक्ताओं के परिसरों में अविलम्ब मीटर लगवाया जाय।

(ग) जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि उनके स्तर सेहोने वाली समीक्षा बैठक में विद्युत् आपूर्ति और परियोजनाओं के कार्यों की भी समीक्षा किया जाय।

<u>जिला पदाधिकारियों द्वारा बैठक में रखे गये महत्वपूर्ण बिन्दु :–</u>

6. जिला पदाधिकारी, जमुई ने कहा कि वर्षा के कारण हाउस होल्ड सर्वे का कार्य बाधित था। पिछले 4–5 दिनों से सर्वे का कार्य पुनः शुरु हुआ है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा गया कि वर्षा के कारण जमुई में सर्वेक्षण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए था। इस पर जिला पदाधिकारी व्यक्तिगत ध्यान केन्द्रित कर समय पर कार्य पूरा करायें।

7. उप समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा बताया गया कि बाढ़ के कारण पिछले 10 दिनों से हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रभावित था। 5–6 दिनों से कार्य में तेजी आई है। राधोपुर में कार्य की गति तेज है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा सर्वे के कार्य पर विशेष ध्यान देकर कार्य समय पर पूरा करने के लिए निदेश दिया गया।

8. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा बताया कि सर्वे के कार्य में 4–5 दिनों का gap हुआ था, अब तेजी आई है।

9. दरभंगा प्रमण्डल के प्रमण्डलीय आयुक्त ने बताया कि जिले में 18 से 20 घंटे तक बिजली मिलती है, परन्तु ट्रिपिंग की समस्या है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

10. जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य प्रगति पर है। समय पर सर्वे कार्य पूरा करा लिया जायेगा।

11. जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा कहा गया कि बिक्रमगंज में जर्जर तार को maintenance कराने की आवश्यकता है। विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता ने बताया कि VCB में तकनीकी खराबी थी, इसे ठीक कर लिया गया है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक ने निदेश दिया कि जर्जर तारों की maintenance की समस्या का संबंधित विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता द्वारा शीघ्र समाधान किया जाय।

12. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि स्पॉट बिलिंग हेतु एजेंसी द्वारा पर्याप्त संख्या में manpower उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को ससमय विपत्र उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। इस संदर्भ में एजेंसी को भी जिला स्तर के समीक्षा बैठक में कई बार कहा जा चुका है। महाप्रबंधक (राजस्व) को इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

13. जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा कोचाधामन और टेढ़ागाछ के लिए एक–एक कनीय विद्युत् अभियन्ता के पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया।

14. जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि विद्युत् परियोजना का कार्य, एजेंसी द्वारा वन विभाग को पैसा जमा नहीं किये जाने के कारण बाधित हो रहा है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्तर पर वन विभाग से ऐसे स्थानों का NOC प्राप्त करने की कार्रवाई को take up किया जायेगा।

15. जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि पिछले पाँच दिनों से हाउस होल्ड सर्वे के कार्य में तेजी आयी है और लक्ष्य को समय पर पूरा कर लिया जायेगा।

16. जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि बाढ़ के कारण हाउस होल्ड सर्वे का कार्य नहीं हो रहा था। अब बाढ़ खत्म हो गया है अतः सर्वे का कार्य समय पर पूरा कर लिया जायेगा।

17. सारण प्रमण्डल के आयुक्त द्वारा बताया गया कि जिले में 16–18 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जाती है, लेकिन विद्युत आपूर्त्ति निर्बाध नहीं रहती है।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताया गया कि संचरण अवरोधों के कारण पावर सब–स्टेशन को भरपूर बिजली नहीं मिलती है। दिसम्बर, 2016 तक 220/132/33 के०वी० अमनौर, ग्रिड उपकेन्द्र कार्य करना शुरु कर देगा। इससे सिवान, बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर की बिजली की समस्या दूर हो जायेगी।

18. अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताया गया कि सिवान, गोपालगंज और छपरा में दशहरा तक बिजली आपूर्ति की दिशा में काफी सुधार हो जायेगा।

19. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा कहा गया कि जिले को दिये गये लक्ष्य मेंहाउसहोल्ड की संख्या अधिक है।

प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि लक्ष्य का निर्धारण Census डाटा के अनुसार ही किया गया है। इसे जिलाधिकारी अपने स्तर से Census के अनुसार सत्यापित कर सुधार कर सकते हैं एवं सुधार के उपरान्त बदले हुए लक्ष्य से कम्पनी मुख्यालय को अवगत करा दिया जाय।

20. जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा बताया गया कि चार नये सब–स्टेशन बनाने के लिए प्रस्ताव आया है। नये सब–स्टेशन के लिए जमीन की स्वीकृति हेतु जिला स्तर से प्रयास किया जा रहे हैं।

21. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया कि जमुई GSS में 50 MVA के ट्रान्सफॉरमर की आवश्यकता है जिसके कारण मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है। उन्होंने यह भी कहा कि नदी किनारे 33 के०वी० का लाईन खींचा जा रहा था, उसका कार्य अभी बन्द है।

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि दशहरा के पहले नये ट्रान्सफॉरमर को चालू कर दिया जाय। जानकारी दी गई कि 33 के०वी० लाईन के लिए टेन्डर कर दिया गया है, शीघ्र ही कार्य शुरु हो जायेगा।

22. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि नये पावर सब–स्टेशन के लिए जमीन की आवश्यकता होगी।

सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध है, वहाँ पहले जमीन उपलब्ध कराकर PSS/GSS बनवाने का काम शुरु करवा दिया जाय तथा जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ निजी जमीन को

लीज पॉलिसी के अन्तर्गत भूमि का चयन कर भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह०/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग, पटना।

ज्ञापांक– प्र०2/विविध वि०कं०–18/13– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक– प्र०2/विविध वि०कं०–18/13– 2997 पटना, दिनांक– 07/10/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,